प्रकाशन का 46 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई-पेपर

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

www.facebook.com/shailsamachar

वर्ष 46 अंक-52 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पर्जीकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 20-27 दिसम्बर 2021 मूल्य पांच रूपए

प्रधानमंत्री की सभा में लोग लाने की जिम्मेदारी लगी प्रशासन के नाम

- लाभार्थियों के नाम पर मुख्य सचिव को लिखना पड़ा पत्र
- कांग्रेस के समय की योजनाओं के हो रहे उद्घाटन शिलान्यास
- सावड़ा कुडू का 19-6-2005 को वीरभद्र ने किया था उद्घाटन
- केंद्र द्वारा दी गई 72000 करोड़ की सहायता पर उठे सवाल
- मंत्रिमंडल की पहली बैठक में किए भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के वादे का क्या हुआ
- कांग्रेस के अंतिम छः माह के फैसलों की समीक्षा कहां रह गयी

शिमला/शैल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित मण्डी यात्रा के अवसर पर जयराम सरकार ने बड़े-बड़े विज्ञापन जारी करके प्रदेश की जनता को यह जानकारी दी है कि इस अवसर पर 210 मेगावाट की लूहरी, 66 मेगावाट की धौलासिद्ध, 111 मेगावाट की सावड़ा कुडू और 143 मेगावाट की रेणुका सागर पनबजली परियोजना के उद्घाटन/शिलान्यास करेंगे। इन योजनाओं के लिये जयराम सरकार ने कितना काम किया है और केंद्र की मोदी सरकार ने कितनी आर्थिक सहायता दी है इसका कोई ब्योरा जारी नहीं किया गया जिसके लिये आज श्रेय लिया जाये। क्योंकि सावड़ा कुडू परियोजना एशियन विकास बैंक के सहयोग से बनी है और जनवरी 2021 से उत्पादन में आकर अब तक 120 करोड़ की बिजली बेच भी चुकी है। इस परियोजना की आधारशिला स्व. वीरभद्र सिंह ने 19 जून 2005 को रखी थी। धौलासिद्ध और लूहरी दोनों का काम एसजेवीएनएल के पास है और एक एक डायवर्जन टनल तैयार हो चुकी है। इसी तरह रेणुका सागर बांध परियोजना का काम भी काफी समय से चला हुआ है। 2018 से ही कई बैठकें हो चुकी हैं। कुल मिलाकर यह सारी योजनाएं ऐसी हैं जिनका कोई उदघाटन /शिलान्यास इस समय नहीं बनता है। लेकिन जयराम सरकार प्रधानमंत्री से यह सब करवाने जा रही है। स्वभाविक है कि प्रधानमंत्री को इस की व्यवहारिक जानकारी न हो और उनसे केवल अपनी पीठ थपथपाना ही इसका उद्देश्य रहा हो। लेकिन प्रदेश की जनता तो यह सब जानती है और वह इस पर किसी भी तरह गुमराह नहीं होगी। राजनीतिक विश्लेषकों की नजर में चुनावी वर्ष में इस तरह के कामों से कोई लाभ नहीं मिलेगा बल्कि इससे प्रधानमंत्री की छवि को भी ठेस पहुंचेगी।

बल्कि इस अवसर पर यह सवाल पूछा जायेगा कि 2017 के चुनाव से पहले घोषित 69 राष्ट्रीय राजमार्गों का क्या हुआ है। स्मरणीय है कि इन राजमार्गों की जानकारी प्रदेश की जनता को जगत प्रकाश नड्डा ने यह कह कर दी थी कि उन्हें इस आशय की गडकरी के यहां से पत्र मिला है। लेकिन आज यह राजमार्ग प्रदेश की जनता के साथ एक मजाक साबित हुये हैं। 2017 के चुनाव में ही मण्डी की एक जनसभा में प्रधानमंत्री ने स्व. वीरभद्र सिंह से प्रदेश को दिये गये 72000 करोड़ का हिसाब मांगने की बात की थी। यही नहीं 2019 के चुनावों में गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी रैली में केंद्र से मिली सहायता का आंकड़ा 2,30,000 करोड़ बताया है। लेकिन आज तक जयराम सहायता के इन आंकड़ों को प्रदेश की जनता के सामने नहीं रख पायी है। आने वाले विधानसभा चुनाव में यदि प्रदेश के हर मतदाता ने यह सवाल पूछने शुरू कर दिये तो सरकार के सामने एक ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जायेगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। क्योंकि 2017 का 46,500 करोड का कर्ज बढ़कर आज 70,000 करोड़ तक पहुंच रहा है। दूसरी ओर 2019-20 की आई कैग रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है की सरकार ने 96 योजनाओं में एक फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं की और न ही इसका कोई कारण बताया है। इस खुलासे से यही सामने आता है कि सरकार यही समझती है कि जनता उसकी हर बात पर आंख मूंदकर विश्वास कर लेती है।

इस अवसर पर यह स्मरण करना भी आवश्यक हो जाता है कि जयराम सरकार ने अपने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में जनता से क्या वायदे किये थे। उल्लेखनीय है कि जनवरी 2018 की पहली की बैठक में यह वायदा किया था कि भ्रष्टाचार कतई सहन नहीं होगा। इस वायदे की पूर्ति में अपने ही सौंपे किसी आरोप पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं कर पायी है। जिस बिवरेज कॉरपोरेशन को लेकर बड़ा आडंबर खड़ा किया गया था उसका क्या हुआ। इसकी कोई आधिकारिक जानकारी बाहर नहीं आयी। पहली बैठक में यह कहा गया था कि कांग्रेस सरकार द्वारा पिछले 6 माह में लिये गये फैसलों की समीक्षा होगी और गलत फैसलों को बदला जायेगा। लेकिन 4 वर्षों में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है कि कांग्रेस का यह फैसला गलत था और इसे बदला गया है। इसी बैठक में यह भी फैसला लिया गया था कि सरकार हर विभाग को 100 दिन की कार्ययोजना बनाने के लिए कहे और फिर उसकी समीक्षा करेगी। पहली बैठक में उद्योगों को 5 वर्ष के लिए करों में सौ प्रतिशत छूट की भी घोषणा की गयी थी लेकिन इस घोषणा के बावजूद हर वर्ष कर राजस्व में बढ़ोतरी हुई है जिसका अर्थ है कि आम आदमी पर करों का बोझ बढ़ाया जा रहा है। शायद इन्हीं नीतियों का परिणाम है कि आज प्रधानमंत्री की जनसभा में लोगों को लाने की जिम्मेदारी प्रशासन को सौंपी गई है। और इसके लिए मुख्य सचिव को लिखित में आदेश जारी करने पड़े। लोगों को लाने उनको ठहराने और उनके खाने की व्यवस्था प्रशासन को करनी पड़ रही है। जब इस पर विपक्ष ने सवाल उठाया तो भाजपा की ओर से यह कहा गया कि राहुल गांधी की रैली के लिए कांग्रेस ने भी ऐसा ही किया था। इससे यह सवाल उठना शुरू हो गया है कि क्या भाजपा ने यह वादा किया था कि वह कांग्रेस से भी बड़े भ्रष्टाचार करेगी।

111 मेगावाट सावड़ा- कुडडू विद्युत परियोजना- पूर्व कांग्रेस सरकार की देन

यह तस्वीरें 19 जून 2005 की है

पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह, पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीमती विद्या स्टोक्स और श्री रोहित ठाकुर विधायक जुब्बल-नावर-कोटखाई ने सावड़ा-कुडडू विद्युत परियोजना 111 मेगावाट की आधारशिला 19 जून, 2005 को रखी थी। इस परियोजना को एशियन विकास बैंक के माध्यम से स्वीकृत करवाया गया था और इस योजना में ₹2100 करोड़ रुपए ख़र्च हुए हैं।

राज्यपाल ने श्रवण एवं दृष्टिबाधित स्कूल सुन्दरनगर का दौरा किया

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने मण्डी जिला के सुन्दरनगर में श्रवण एवं दृष्टिबाधित स्कूल सुन्दरनगर का दौरा किया।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि इस संस्थान में अध्ययनरत बच्चे विशेष हैं क्योंकि इनमें विशेष गुण हैं। उन्होंने कहा कि सभी का दायित्व है कि इन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए

समान अवसर प्रदान किए जायें। ये बच्चे योग्य और बुद्धिमान हैं। इन बच्चों से हमें ये समझने की प्रेरणा मिलती है कि जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कैसे बढ़ा जा सकता है।

राज्यपाल ने अपनी ऐच्छिक निधि से संस्थान के लिए एक लाख रुपये प्रदान करने की घोषणा भी की। उन्होंने संस्थान में स्मार्ट कक्षाएं आरम्भ करने की घोषणा भी की।

इस अवसर पर राज्यपाल ने विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। विद्यार्थियों ने उनसे जानना चाहा कि आपको हिमाचल कैसा लगा तो राज्यपाल ने बताया कि मुझे हिमाचल उतना ही पसन्द है जितना की आपको और वह यहां ऐसा अनुभव करते हैं जैसे वह अपने घर गोवा में हों। उन्होंने कहा कि वह मण्डी में पहली बार आए हैं और यहां बार-बार आना चाहेंगे।

राज्यपाल ने संस्थान के आवासीय क्षेत्र का दौरा भी किया और यहां विभिन्न प्रबन्धों का जायजा लिया।

अस्पताल कल्याण अनुभाग, राज्य रेडक्रॉस सोसायटी की अध्यक्ष और भारतीय रेडक्रॉस बोर्ड की सदस्य डॉ. साधना ठाकुर ने कहा कि उनका सौभाग्य है कि उन्हें इन बच्चों का सान्निध्य प्राप्त हुआ। इन छात्रों ने अपनी लगन और प्रतिभा से सभी को प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि इन विद्यार्थियों की भाषा का ज्ञान पाकर इनसे और बेहतर तरीके से संवाद किया जा सकता है और इसके लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाने चाहिए। उन्होंने संबंधित विभाग को इस बारे में कार्य करने का सुझाव दिया।

राज्यपाल के सचिव एवं अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण विभाग के निदेशक विवेक भाटिया ने राज्यपाल का स्वागत किया और संस्थान में आने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि विशेष छात्रों के लिए उनका आशीर्वाद एक प्रेरणा है।

संस्थान की प्रधानाचार्य नीलम में राज्यपाल का स्वागत किया और उन्हें संस्थान की विभिन्न गतिविधियों से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि 1990 में स्थापित इस संस्था में वर्तमान में 111 छात्राएं अध्ययनरत हैं।

इससे पूर्व, सुन्दरनगर हेलीपैड में आगमन पर जिला प्रशासन ने राज्यपाल का स्वागत किया। राज्यपाल ने उपायुक्त मण्डी अरिन्दम चौधरी, पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री और अन्य अधिकारियों के साथ बीबीएमबी अतिथि गृह सुन्दरनगर मण्डी में विभिन्न विषयों पर चर्चा की।

इस अवसर पर स्कूल की छात्राओं ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया।

जनगणना कार्य मे व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाये:राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से राजभवन में जनगणना कार्य निदेशालय, हिमाचल प्रदेश के निदेशक सुशील कप्टा ने भेंट की।

राज्यपाल ने कहा कि जनगणना कार्य के दौरान व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा व गोपनीयता बनाये रखने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने जनगणना का कार्य आरंभ होने पर लोगों को इस बारे में अधिक से अधिक जागरूक करने की आवश्यकता पर बल दिया।

सुशील कप्टा ने राज्यपाल को जनगणना कार्य निदेशालय की कार्यप्रणाली से अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि जनगणना 2021 भारत की प्रथम डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें डेटा एकत्र करने के लिए पहली बार मोबाइल एप्प का उपयोग किया जाएगा। जनगणना 2021 में स्वयं गणना का प्रावधान भी होगा। यह भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के अनुरूप है। उन्होंने बताया कि जनगणना 2021 के प्रबंधन और निगरानी के लिए समर्पित जनगणना पोर्टल भी विकसित किया गया है।

इस अवसर पर जनगणना कार्य निदेशालय के उप-निदेशक राजेंद्र प्रसाद और आशीष चौहान भी उपस्थित थे।

आलू से बनने वाले उत्पादों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए:राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से राज भवन में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला के निदेशक एन. के. पाडे ने भेंट की और उन्हें संस्थान की विभिन्न गतिविधियों से अवगत करवाया।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि आलू से बनने वाले विभिन्न तरह के उत्पादों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, इससे किसानों की आर्थिकी और अधिक सुदृढ़ होगी। उन्होंने कहा कि आलू के उपयोग को लेकर फैली विभिन्न भ्रांतियों को दूर करने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि इस संस्थान द्वारा आलू की 66 विभिन्न किस्में तैयार की गयी हैं जिसमें से 8 किस्मों का प्रसंस्करण किया जा सकता है।

इसके उपरान्त, राष्ट्रीय लेखा परीक्षा एवं लेखा अकादमी के महानिदेशक सुनील एस. दाढ़े ने भी राज्यपाल से भेंट की। यह एक शिष्टाचार भेंट थी।

राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयन्ती पर रिज शिमला स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन के प्रवर्तक थे। उन्होंने कहा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने तो कई वर्षों बाद देशवासियों ने स्वराज का रूपांतरण सुराज में होते देखा।

उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की प्रेरणा से हम जन भागीदारी और सुशासन के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने भारत को मजबूत बनाने और विकसित करने में अपना जीवन समर्पित कर दिया था। राष्ट्र के लिए उनके बहुमूल्य योगदान को लोग हमेशा याद रखेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी एक ख्याति प्राप्त दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने नेतृत्व के उच्चतम मूल्य स्थापित किए और भविष्य में भी देश के विकास के लिए उनके योगदान को याद रखा जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी एक उत्कृष्ट वक्ता थे, उनमें श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देने की क्षमता थी।

उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी के लिए देश सर्वप्रथम था इसलिए वह देशवासियों द्वारा सच्चे राजनीतिज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। उनके विचार और देश की प्रगति के लिए उनका समर्पण हमें सदैव राष्ट्र सेवा के लिए शक्ति देता रहेगा।

इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, नगर निगम शिमला की महापौर सत्या कौंडल, उप महापौर शैलेन्द्र चौहान, पार्षदगण, उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी, पुलिस अधीक्षक डॉ. मोनिका, वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।

राज्यपाल ने लक्ष्मी नारायण मंदिर कुसुम्पटी में पूजा-अर्चना की

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने हिमाचल प्रदेश आरोग्य भारती द्वारा शिमला के उपनगर कुसुम्पटी में तुलसी पूजा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने गरीब लोगों को राज्य रेडक्रॉस द्वारा उपलब्ध करवाये गये कंबल वितरित किये।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि तुलसी का पौधा हर घर में बांटे जाने के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाने चाहिए। तुलसी का पूजन हमारी संस्कृति की उच्च परम्परा हैं और यह पौधा स्वास्थ्य की दृष्टि से भी जीवनदायनी माना गया है। उन्होंने कहा कि रेडक्रॉस हमेशा से गरीब और पीड़ित मानवता की सेवा में तत्पर रहता है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल देवभूमि है और यहां रहने वाले लोग देव स्वरूप मानव हैं। उन्होंने कहा कि यहां के लोगों ने मुझे अल्पावधि में ही बहुत स्नेह दिया और यह उन्हें अधिक कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि वह लोगों के सहयोग से समाज सेवा के कार्यों को और बढ़ाने का प्रयास करेंगे।

इससे पूर्व, राज्यपाल ने लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा-अर्चना भी की।

इस अवसर पर आरोग्य भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राकेश पंडित ने राज्यपाल को सम्मानित किया तथा कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादकःजे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकारः ऋचा
अन्य सहयोगी
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
INVITATION FOR BIDS (IFB)

The Executive Engineer HPPWD Division Hamirpur Distt. Hamirpur H.P on behalf of Governor of H.P invites the item rate bids, in electronic tendering system from the eligible class for the works as detailed in the table.

Sr.No. Name of Work	Estimated cost (In Rs.)	Starting Date of downloading Bid	Earnest Money (In Rs.)	Deadline for submission of Bid
1. C/o Sour, Chowkar to Aghar road km 0/0 to 2/0. (SH:- Construction of Retaining wall at RD 0/141 to 0/191) under MMGSY.	717936.00	31.12.2021	14400.00	07.01.2022
2. Construction of link road from Neri Shodh Sansthan to Kamlah via Bardu Pounta km 0/0 to 0/600. (SH:- ROFD and C/o 900mm dia Hume Pipe Culvert at various RDs from km 0/0 to 0/660).	1487631.00	31.12.2021	29800.00	07.01.2022
3.S/R to Chief Engineer office at Hamirpur. (SH:- P/F Cup Board , Paneling in S.E. and E.E. rooms, C/O store room in Basement, P/F vitrified tile in stair case/corridor, painting and distempering etc.	2313619.00	31.12.2021	42300.00	07.01.2022
4. S/R to Type-III Quarters in Rental Housing Board Colony at Hamirpur. (SH:- Painting, distempering, tile flooring in kitchen, bath room and W.C. in quarter No. 5 to 12).	1891147.00	31.12.2021	35900.00	07.01.2022

The bidders are advised to note other details of tenders from the department website www.hptenders.gov.in.

Adv. No. 5826/21-22 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

मुख्यमंत्री ने कुल्लू में ईट राइट मेले का शुभारम्भ किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कुल्लू के ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में 'ईट राइट' मेले का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर

आयोजित जनसभा को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 27 दिसम्बर, 2021 को वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल के चार वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मण्डी में आयोजित होने वाली विशाल जनसभा को सम्बोधित करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 दिसम्बर को मण्डी में 11,279 करोड़ रुपये लागत की विकासात्मक परियोजनायें प्रदेशवासियों को समर्पित करेंगे।

मुख्यमंत्री ने ईट राइट मेले कुल्लू के आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए सन्तुलित आहार बहुत आवश्यक होता है। सन्तुलित भोजन ग्रहण करने से ही स्वस्थ जीवनशैली का विकास होता है। प्रदेश सरकार द्वारा बच्चों और महिलाओं को पोषणयुक्त आहार प्रदान करने के लिए कई कार्यक्रम आरम्भ किए गए हैं। पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत प्रदेश के 78 विकास खण्डों में 18,925 आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से छः माह से छः वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री माताओं कुपोषित बच्चों को पूरक पोषाहार उपलब्ध करवाया जा रहा है। पूरक पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित किए जा रहे लाभार्थियों को बाल पोषाहार टॉप-अप योजना जो राज्य संचालित योजना है के तहत भी लाभान्वित किया जा रहा है। प्रदेश में आंगनवाड़ी केन्द्रों में पोषण अभियान के तहत हर माह एक व 15 तारीख को समुदाय आधारित कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है।

इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों, स्वयं सहायता समूहों तथा स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा लगाई गयी प्रदर्शनियों का अवलोकन किया।

शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि चार वर्ष के कार्यकाल के दौरान प्रदेश सरकार द्वारा समाज के हर वर्ग और क्षेत्र का समान एवं संतुलित विकास सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने कहा कि ईट राइट मेले के दौरान लोगों को स्वस्थ एवं संतुलित आहार की जानकारी प्राप्त होगी।

इस अवसर पर विधायक किशोरी लाल सागर और सुरेन्द्र शौरी, पूर्व सांसद महेश्वर सिंह, भाजपा नेता ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने मंडी में शिवधाम के निर्माण कार्यों की समीक्षा की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने मंडी के निकट कंगनीधार में प्रस्तावित शिवधाम के निर्माण कार्यों का

जायजा लिया और इस महत्वाकांक्षी परियोजना के प्रगति कार्य की समीक्षा की। इस परियोजना का प्रथम चरण लगभग 40 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण होगा।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस परियोजना का कार्य समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए ताकि इस परियोजना की लागत में वृद्धि से बचा सके। उन्होंने कहा कि यह परियोजना हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा नई राहें नई मंजिलें योजना के अन्तर्गत क्रियान्वित की जा रही है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि यह परियोजना पूर्ण होने के बाद प्रदेश में आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होगी। इसमें 12 ज्योर्तिलिंगों की प्रतिकृतियां स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगले साल जुलाई के अन्त तक इस परियोजना के पूर्ण होने का अनुमान है। मंडी के उपायुक्त अरिंदम चौधरी और हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अन्य अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने मनाली में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने जिला कुल्लू स्थित माल रोड़ मनाली में पूर्व प्रधानमंत्री, भारत

रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 97वीं जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया।

इसके उपरांत, मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के गांव प्रीणी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य और विशेष रूप से कुल्लू जिला के लोग भाग्यशाली हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी का हिमाचल के प्रति विशेष स्नेह एवं लगाव था। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद, अटल बिहारी वाजपेयी हर वर्ष प्रीणी आते थे। उन्होंने कहा कि इस छोटे से गांव से कुछ दिनों तक पूरी सरकार चलती थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की विशेष कृपा से राज्य को केंद्र से उदार सहायता प्राप्त हुई है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक विरोधी भी उनके भाषण सुनने आते थे। उन्होंने कहा कि अटल टनल पूर्व प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता का परिणाम है, जिसने जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की अर्थव्यवस्था को बदल दिया है और यह सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि लगभग 3500 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित इस टनल को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 3 अक्तूबर, 2020 को राष्ट्र को समर्पित कर पूर्व प्रधानमंत्री के इस सपने को साकार किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस टनल ने लाहौल स्पीति जिला में विकास का नया मार्ग प्रशस्त किया है। उन्होंने कहा कि इस दिन को पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में राज्य सरकार की कई योजनाओं का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अटल ज्ञान केंद्र योजना को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव मदद प्रदान करेगी क्योंकि यह पूर्व प्रधानमंत्री को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की कविताओं की कुछ पंक्तियां भी सुनाई।

जय राम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार इस महीने की 27 तारीख को अपने वर्तमान कार्यकाल के चार वर्ष पूर्ण कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक पडडल ग्राउंड, मंडी में एक विशाल सभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने लोगों से मेगा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भी आग्रह किया जय राम ठाकुर ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की।

मुख्यमंत्री ने प्रीणी गांव में सामुदायिक केंद्र के निर्माण के लिए 20 लाख रुपये और प्रीणी में जंजघर के निर्माण के लिए 10 लाख रुपये की घोषणा की। उन्होंने स्थानीय युवक मंडल को अपने ऐच्छिक निधि से क्रिकेट और वॉलीबॉल किट खरीदने के लिए 2 लाख रुपये देने की भी घोषणा की।

शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने अपने गृह क्षेत्र में मुख्यमंत्रे का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य के लोग भाग्यशाली हैं कि प्रदेश से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का विशेष स्नेह रहा है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी अटल बिहारी वाजपेयी नियमित रूप से प्रीणी का दौरा करते थे और उनका कुल्लू और प्रीणी के लोगों के साथ उनका विशेष लगाव था। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने मनाली में कई कविताएं लिखी थीं। उन्होंने कहा कि लगभग 44 लाख रुपये की लागत से निर्मित पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा, जिसका मुख्यमंत्रे द्वारा अनावरण किया गया है, वास्तव में अटल बिहारी वाजपेयी को एक सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने क्षेत्र की विभिन्न विकासात्मक मांगों के बारे में भी विस्तार से बताया।

प्रीणी पंचायत की प्रधान कल्पना आचार्य ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया।

स्वास्थ्य मंत्री ने जीसीसीआई मोबाइल यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

शिमला/शैल। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैंसर निवारण कार्यक्रम के तहत ग्लोबल कैंसर कंसर्न इंडिया (जीसीसीआई) मोबाइल यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कार्यक्रम में एसजेवीएन ने सहयोग प्रदान किया है।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कैंसर के लक्षणों के बारे में लोगों में जागरूकता लाना और इसका शीघ्र पता लगाना मोबाइल

कैंसर रोकथाम कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य हैं। उन्होंने कहा कि कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इसका शीघ्र पता लगने से कीमती मानव जीवन को बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मोबाइल यूनिट स्क्रीनिंग के माध्यम से गांवों में जांच शिविर लगाये जायेंगे।

डॉ. राजीव सैजल ने कहा कि सरकार और गैर सरकारी संगठनों को कैंसर देखभाल प्रबंधन के क्षेत्र में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

इस अवसर पर सीएमओ जिला शिमला डॉ सुरेखा, स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, जीसीसीआई के प्रतिनिधि और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे, जबकि जीसीसीआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. हरविंदर सिंह बख्शी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए।

दिव्ययोग संस्थान द्वारा निशुल्क फिजियोथैरेपी शिविर का आयोजन

शिमला/शैल। दिव्ययोग रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा दिव्य फिजियोथैरेपी सैंटर न्यू टूटू, शिमला में 26 से 28 दिसम्बर 2021 तक तीन दिवसीय शिविर लगाने का आयोजन किया जा रहा है। संस्थान द्वारा यह शिविर स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत आम जनता के लिए लगाया जा रहा है तथा यह शिविर सभी के लिए निशुल्क होगा। कोई भी इस सुविधा का लाभ प्रातः 9 से दोपहर 12 बजे तक प्रतिदिन ले सकता है।

दिव्य फिजियोथैरेपी सैंटर में उच्च योग्यताप्राप्त और अनुभवी डा. रजत अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इस शिविर में अर्थराइटस, गठिया, लकवा, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलोसिस, पीठ, कमर, कंधो, घुटने, जोड़ों की दर्द, कम्पन, सुन्नपन, बैलेंस बिगड़ना तथा आप्रेशन के बाद होने वाली समस्याओं के बारे में अवगत करवाया जाएगा और उनके समाधान हेतू परामर्श दिया जाएगा।

दिव्ययोग संस्थान के अध्यक्ष विजयकुमार सूद ने बताया कि संस्थान द्वारा इस प्रकार के स्वास्थ्य संबन्धी कार्यक्रम पिछले कई वर्षो से यदा-कदा किए जाते रहे हैं। इसी कड़ी में इस बार शरीर को सर्दियों के मौसम में भौतिक चिकित्सा द्वारा कैसे दरुस्त व तंदरूस्त रखा जा सकता है इस पर यह शिविर लगाया जा रहा है।

एक समझदार आदमी को सारस की तरह होश से काम लेना चाहिए और जगह, वक्त और अपनी योग्यता को समझते हुए अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए।......चाणक्य

सम्पादकीय

क्या चुनाव टालने की भूमिका बनाई जा रही है

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शेखर यादव ने अपने एक आदेश में देश के चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव दो-एक माह के लिये टाल दिये जायें। मान्य न्यायधीश ने यह आग्रह अपनी अदालत में वकीलों की भीड़ और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपाल न होने के कारण किया है। अदालत का यह तर्क रहा है कि आमीक्राम वायरस जिस तेजी से बढ़ रहा है उसके परिदृश्य में प्रदेश विधानसभा के चुनाव करवाना सही नहीं होगा। क्योंकि चुनावी रैलियों में भीड़ होगी और उसमें मानकों का पालन संभव नहीं होगा। जस्टिस शेखर कुमार यादव ने यह चिन्ता इस वायरस के संक्रमण की तीसरी लहर फरवरी में आने की संभावना के परिदृश्य में की है। जबकि ऐसी कोई याचिका उनके पास सुनवाई के लिए लंबित नहीं थी। जस्टिस शेखर यादव का यह फैसला उसी तर्ज का है जैसा कि मेघालय उच्च न्यायालय के जस्टिस सेन का फैसला था कि अब देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाना चाहिये और यह काम आदरणीय नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। जस्टिस एसआर सेन के फैसले के खिलाफ सी पी एम और नेशनल कॉन्फ्रेंस आदि सर्वोच्च न्यायालय में भी पहुंचे थे। जस्टिस रंजन गोगोई और संजीव खन्ना की पीठ ने नोटिस भी जारी किये थे। लेकिन बाद में यह कह दिया गया था कि इसमें कुछ भी करने की जरूरत नही हैं। लेकिन इसी फैसले के बाद नागरिकता अधिनियम संशोधन आया और फिर संघ प्रमुख मोहन भागवत के नाम से ''भारत का नया संविधान'' की भूमिका वायरल हुई। यह प्रस्तावित संविधान पूरी तरह हिंदुत्व की अवधारणा पर आधारित है। लेकिन इसका कोई खंडन न तो संघ- मोहन भागवत और न ही भारत सरकार की ओर से आया है। इस परिपेक्ष में मान्य उच्च न्यायालय में के मान्य न्यायाधीशों के इस तरह के फैसलों को हल्के से नहीं लिया जा सकता।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद यह चर्चा चल पड़ी है कि क्या सरकार पांच राज्यों में होने वाले चुनावों को टालने की योजना बना रही है। उत्तर प्रदेश की चुनावी अहमियत इसी धारणा से पता चल जाती है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। जिस उत्तर प्रदेश में 2017 और 2019 के चुनावों के बाद यह कहा जाने लगा था कि उसे वहां पर कोई चुनौती ही नहीं बनी है वहां पर आज जिस तरह की भीड़ अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की जनसभाओं में उमड रही है उससे भाजपा के माथे पर चिंता की लकीरें साफ उभरना शुरू हो गयी हैं। क्योंकि इसी अनुपात में अब प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष नड्डा की सभाओं में खाली कुर्सियां दिखनी शुरू हो गयी है। प्रियंका और राहुल के प्रयासों से कांग्रेस ने मुकाबले को तिकोना बना दिया है। फिर अयोध्या, काशी और मथुरा के प्रयोगों से भी धार्मिक और जातीय धुव्रीकरण नहीं बन पाया है। लखीमपुर खीरी कांड के बाद भी किसान आंदोलन हिंसा न हो पाना इसी कड़ी में देखा जा रहा है। बल्कि इस काण्ड पर आई एस आई टी की रिपोर्ट के बाद गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा भाजपा का नैगेटिव बनता जा रहा है। राम मंदिर के लिये की गई जमीन में लगे घोटाले के आरोपों का अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। महंगाई और बेरोजगारी से जिस कदर आम आदमी पीड़ित हो उठा है उससे किसी भी तरह के धुव्रीकरण के प्रयास सफल नहीं हो रहे हैं। ऊपर से अब कृषि मंत्री तोमर का यह ब्यान कि सरकार कृषि कानूनों को लेकर फिर से एक प्रयास करेगी से स्थिति और उलझ गयी है। बल्कि इस ब्यान के बाद ममता बनर्जी के लिये भी अदानी के साथ बन रहे रिश्तो पर जवाब देना कठिन हो जायेगा। इस सब को अगर एक साथ मिलाकर देखा जाये तो स्पष्ट हो जाता है कि यू पी में भाजपा की राह लगातार कठिन होती जा रही है और इससे एक दम बाहर निकलने के लिए ओमीक्राम के खतरे का नाम पर चुनाव टालने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं रह जाता है।

पांच राज्यों के लिये हो रहे चुनावों को लेकर सर्वे आ रहे हैं उनके मुताबिक कहीं भी भाजपा सुखद स्थिति में नहीं है। उत्तराखंड में भाजपा के कई मंत्री और विधायक कांग्रेस में वापसी कर चुके हैं। पंजाब में भाजपा को उस अमरिंदर सिंह का दामन थामना पड़ रहा है जो कांग्रेस छोड़ने के बाद पटियाला में ही अपने आदमी को मेयर का चुनाव नहीं जीतवा पाये। बंगाल की हार से प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत साख को जो धक्का पहुंचा है उससे अभी तक बाहर नहीं निकल पाये हैं। इस लिए अभी ओमीक्राम के नाम पर छः माह के लिए चुनाव टालने की भूमिका बनाई जा रही है। कुछ राज्यों द्वारा रात्रि कर्फ्यू लगाया जाना इसी दिशा का प्रयास है। यदि एक बार चुनाव टाल दिये जाते हैं तो इन राज्यों में अपने आप ही राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति आ जायेगी। जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में महामारी अधिनियम और महामारी की व्यवहारिकता को लेकर एक चर्चा की आवश्यकता हो जाती है और इसे अगले अंक में उठाया जायेगा।

यूरोपीय सूर्योपासना उत्सव है विंटर सोल्सटिस, जिसे क्रिसमस के रूप में कायांतरित कर दिए पोप जुलियस

गौतम चौधरी

विगत दो दिनों से पूरा ईसाई जगत अपने पवित्र प्रभु के बेटे जीसस के शुभागमन उत्सव, क्रिसमस में डूबा हुआ है। दुनियाभर के मसीही विश्वासी, मसलन ईसाई धर्मावलंबियों के मुख्यालय कहे जाने वाले वेटिकन से पोप प्रेम, करुणा, कोमलता का संदेश के साथ ही बुजुर्गों के प्रति सकारात्मकता का संदेश प्रसारित कर चुके हैं। ईसाई हो या नहीं लेकिन इन दिनों पूरी दुनिया क्राइस्टमैय दिख रहा है लेकिन जिस यूरोप की धरती से येशु के जन्म के उत्सव का संदेश पोप प्रसारित किए उसी यूरोप के एक छोटे से स्थान, सेलिसबरी में अभी दो दिन पहले हजारों लोग जुटे और विंटर सोल्सटिस नामक पर्व मनाया। इतिहासकार बताते हैं कि ब्रिटेन के सेलिसबरी में यह पर्व विगत पांच हजार साल से मनाया जा रहा है। 10 20 से लेकर 31 दिसंबर तक चलने वाले इस पर्व को सूर्योपासना से जोड़ा जाता है और यहां आने वाले लोगों की मान्यता है कि स्ओनहेंज के पत्थरों से लिपटने से फसल अच्छी होती है जीवन में उन्नति मिलती है। यहां आने वाले लोग सूर्य की पहली किरण पाने के लिए लालायित रहते हैं। स्ओनहेंज के पत्थरों के पास पूर्व दिशा में खड़े होकर सूर्योदय की प्रतीक्षा करते हैं। ये कौन लोग हैं और इस पर्व को क्यों मनाते हैं इसके बारे में दुनिया के लोग अनभिज्ञ हैं लेकिन ईसाई चिंतन के ही एक संप्रदाय के द्वारा जीसस के जन्म दिन पर विवाद खड़ा करने के बाद इस बात को बल मिलने लगता है कि यूरोप के लोग ईसाई बनने से पहले मूर्तिपूजक थे और सूर्योपासना की प्रथा पूरे यूरोप में प्रचलित थी।

रांची के बरियातू रोड पर एक चर्च है। यहां के ख्रिस्ती विश्वासी क्रिसमस का त्योहार नहीं मनाते हैं। इस प्रकार के चर्च दुनिया भर में हजारों की संख्या में होंगे लेकिन ये प्रभु के पवित्र पुत्र जीसस का जन्मोत्सव क्यों नहीं मनाते हैं, इसका सीधा संबंध ब्रितानी सेलिसबरी के उस स्टोनहेंज से है जो हजारों साल पुरानी है। खिर्ती विश्वासी में से सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च और चर्च ऑफ क्राइस्ट ऐसा संप्रदाय है जो जीसस का जन्मोत्सव, यानी क्रिसमस नहीं मनाता है। इन विश्वासियों का तर्क है कि बाइबिल में ईसा मसीह के जन्म की कोई तारीख का उल्लेख नहीं है। इन विश्वासियों का यह भी मानना है कि बेबीलोन से क्रिसमस की परंपरा आई जो यूरोप में प्रचलित हो गयी और चैथी शताब्दी के बाद उसी परंपरा को जीसस के जन्मोत्सव के साथ जोड़ दिया गया। इनका मामना है कि क्रिसमस मनाना बेबोलियन रिवाजों को ईसाइयत के आध्यात्मिक आदर्शों पर थोपना है।

सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट विश्वासी क्रिसमस के दिन न तो कोई आराधना करते और न ही यहां के अनुयायी किसी को हैप्पी क्रिसमस या मेरी क्रिसमस कहते हैं। इस संप्रदाय के वरिष्ठ याजक डॉ. जे एम कुजूर कहते हैं कि हमारी आस्था का एकमात्र स्रोत बाइबल है। बाइबल के न्यू टेस्टामेंट के चार समाचारों में ईसा मसीह की जीवनी है। ये चारों सुसमाचार मार्क्स, मैथ्यू, ल्यूक और जॉन द्वारा लिखे गए हैं। इनमें से किसी में ईसा की जन्म की तारीख नहीं बताई गई है। न्यू टेस्टामेंट में ईसा के स्वर्गारोहण के 300 साल बाद तक की घटनाओं का उल्लेख है। कहीं भी क्रिसमस मनाने की कोई चर्चा नहीं है। यहां तक कि 300 साल बाद तक के दृष्टांत में भी ईसा मसीह के जन्म की तारीख बाइबिल नहीं बताती है। काई भी ऐतिहासिक तथ्य ईसा का जन्म 25 दिसंबर को होने की पुष्टि नहीं करते हैं।

जे एम कुजूर कहते हैं कि बेबीलोन में निमरोद नामक एक राजा हुआ। उसने अपने बेटे को चमत्कारी कहना शुरू किया और जनता को अपने बेटे का जन्मदिन मनाने के लिए बाध्य किया। उसके बेटे का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था। बेबीलोन की जनता राजा के डर से उसके बेटे का जन्मदिन 25 दिसंबर को मनाने के साथ ही उसकी पत्नी की गोद में उसके बेटे की मूर्ति रखकर पूजा भी करने लगी। सालों साल की परंपरा ईसाइयत ग्रहण के बाद भी बरकरार रही। बेबीलोन से यह रोम पहुंचा। रोमन सम्राट कांटेस्टाइन के समय में ही ईसाई धर्म को राजधर्म घोषित करने के बाद 25 दिसंबर को ईसा का जन्म दिन क्रिसमस के रूप में मनाया जाने लगा। वहीं निमरोद की पत्नी और बेटे की मूर्ति को लोग मदर मेरी और जीसस की मूर्ति मानकर घरों में स्थापित करने लगे।

पास्टर कुजूर कहते हैं कि यह निर्विवाद तथ्य है कि ईसा का जन्म तब हुआ जब उनके पिता जोसेफ और मां मेरी रोमन सम्राट कैसर के आदेश पर जनगणना में शामिल होने के लिए नाजरथ से यरूशलम जा रहे थे। उसी समय बेथलेहम में खुले आसमान तले सोये गड़ेरियों के बीच उन लोगों ने आसरा पाया और ईसा का जन्म हो गया। पूरे मध्यपूर्व में ऋतुएं एकसाथ आती हैं। यानी दिसंबर के महीने में इजरायल में भी जाड़ा पड़ता है। ऐसे समय में गड़ेरिए खुले आसमान तले नहीं सो सकते हैं। जाहिर है कि जब भी ईसा का जन्म हुआ होगा उस समय गर्मी का मौसम रहा होगा।

पास्टर के तर्क में सच्चाई झलकती है। इस विषय में इतिहासकारों का एक समूह यह भी कहता है कि ईसाइयत के प्रचार से पहले पूरा यूरोप सूर्योपासना का केन्द्र था। ब्रिटेन के सेलिसबरी में स्थित स्टोनहेंज और कुछ नहीं एक ज्योतिषीय प्रतीक है। किसी काल में इसे अंतरिक्ष गणना के लिए बनाया गया है। यह ठीक उसी प्रकार का निर्माण है जैसा भारत के कई शहरों में जंतर-मंतर का निर्माण कराया गया था। अंतरिक्ष गणना के लिए पहले गणना घरों का निर्माण होता था। ब्रितानी पुरातन स्टोनहेंज का पत्थर गणना गृह रहा होगा, जो समय के साथ खंडहरों में बदल गया है लेकिन परंपरा अभी भी यहां जिंदा है। लोग यहां आते हैं और इस बात का सबूत देते हैं कि यह पहले मूर्ति पूजक समाज रहता होगा। यूरोप के कई पुरातात्विक साइट पर आकाश देवी और उसकी गोद में विराजमान सूर्यपुत्र को दिखाता मूर्तियां मिली है। इससे यह साबित होता है कि आकाश देवी और उसी गोद में सूर्य की पूजा यूरोप की पुरानी मान्यताओं में से है। किसी दबाव या लालच में या फिर खुद के विश्वास से लोग अपनी मान्यता और धारणा बदल लेते हैं लेकिन उसकी संस्कृति लंबे समय तक नहीं बदलती। भारत में इसके कई उदाहरण मिल जाते हैं। दूसरी बात यह है कि एकेश्वरवाद का प्रचार तो यूरोप में हो गया लेकिन यूरोप की पुरानी परंपरा और मान्यताओं का रातोंरात बदलना आसान नहीं था। रोम के पोप ने इसके लिए एक तरकीब निकाली और चौथी शताब्दी में यीशु के जन्म की घोषणा कर दी। कहा गया कि 25 दिसंबर को ही प्रभु के पवित्र पुत्र का जन्म हुआ था। इसका न तो कोई धार्मिक प्रमाण है और न ही इतिहासिक प्रमाण। यह केवल और केवल पोप के मनगढ़ंत कपोल कल्पना पर आधारित एक संस्कृति का कायांतरण मात्र है।

बता दें कि एन्नो डोमिनी काल प्रणाली के आधार पर येशु का जन्म 7 इसा पूर्व से 2 ईसा पूर्व के मध्य 4 ईसा पूर्व में हुआ था। जीसस के जन्म का वार, तिथि, मास, वर्ष, समय तथा स्थान, सभी बातें अज्ञात है। इसका बाइबिल में भी कोई उल्लेख नहीं है। ईसाई जगत येशु मसीह का जन्मदिन 25 दिसंबर मानता है, परन्तु विलियम ड्रूरेंट ने येशु मसीह का जन्म वर्ष ईसा पूर्व चौथे वर्ष लिखा है। यह कितनी असंगत बात है कि ईसा का ही जन्म ईसा पूर्व में कैसे हो सकता है, जबकि ईसाई काल गणना येशु मसीह के जन्म से शुरू होती है, और इनके जन्म से पूर्व के काल को ईसा पूर्व कहते हैं और जन्म के बाद की काल की गणना ईस्वी में की जाती है। हैरतअंगेज बात यह भी है कि आज सम्पूर्ण विश्व में ईसा का जन्म 25 दिसम्बर को मनाया जाता है और नववर्ष का दिन होता है एक जनवरी। तो क्या ईसा का जन्म ईस्वी सन् से एक सप्ताह पहले हुआ? यदि हुआ तो उसी दिन से वर्ष गणना शुरू क्यों नहीं की गयी? येशु का जन्म कब हुआ, इसे लेकर विद्वान भी एक राय नहीं हैं।

क्रिसमस के पर्व पर तर्क यह भी दिया जाता है कि प्राचीन काल में 25 दिसम्बर को मकर संक्रांति अर्थात शीतकालीन संक्रांति पर्व मनाया जाता था और यूरोप में धूमधाम से इस दिन सूर्य उपासना की जाती थी, जिसका निक्षेप ब्रिटेन का विंटर सोल्सटिस है। काल वेत्ताओं के अनुसार सूर्य और पृथ्वी की गति के कारण मकर संक्रांति लगभग 80 वर्षों में एक दिन आगे खिसक जाती है। गणना के अनुसार 22 दिसंबर को सूर्य उत्तरायण की ओर व 22 जून को दक्षिणायन की ओर गति करते हैं। यूरोप शीतोष्ण कटिबंध में आता है इसलिए यहां सर्दी बहुत पड़ती है। जब सूर्य उत्तर की ओर चलते हैं तो उत्तरी गोलार्द्ध में सर्दी कम होने की शुरुआत होती है। चूकि यूरोप उत्तरी गोलार्द्ध में है इसलिए यहां के लोग 25 दिसम्बर को मकर संक्रांति मनाते थे। विश्व-कोष में दी गयी जानकारी के अनुसार सूर्य-पूजा को समाप्त करने के उद्देश्य से क्रिसमस डे का प्रारम्भ किया गया था। सबसे पहले 25 दिसम्बर के दिन क्रिसमस का त्यौहार ईसाई रोमन सम्राट के समय में 336 ईस्वी में मनाया गया था। इसके कुछ वर्ष बाद पोप जुलियस ने 25 दिसंबर को ईसा मसीह के जन्म दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी, तब से दुनिया भर में 25 दिसम्बर को क्रिसमस का त्योहार मनाया जाता है।

अटल बिहारी वाजपेयी : सुशासन के पर्याय

– अर्जुन राम मेघवाल –
केन्द्रीय संस्कृति एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री, भारत सरकार एवं लोकसभा सांसद, बीकानेर

शिमला। सुशासन ऐसी धरोहर है जिसे भारत की प्राचीन संस्कृति और लोकाचार से आत्मसात् किया गया है। बौद्ध धर्म के गण संघ, भगवान बासवेश्वकर द्वारा 11वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित अनुभव मंडप, चाणक्य के अर्थशास्त्र, सिधुं घाटी सभ्यता के दौरान नगर योजना, मौर्य सम्राट अशोक की धरोहर के और अन्यत माध्यमों से पुन: संचित प्रजातांत्रिक मूल्य बेहतर सुशासन हेतु विरासत में मिले ज्ञान भंडार हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को मनाने हेतु सुशासन दिवस के अवसर पर, यह अत्यावश्यक है कि हम स्वतंत्र भारत में सर्वोत्तम सुशासन उपायों को संस्थागत बनाने में उनकी असाधारण भूमिका पर प्रकाश डालें और उसे आज के संदर्भ में ग्रहण करें।

स्वतंत्रता के बाद, सुशासन का मुद्दा शासन संबंधी सुधारों का केन्द्र बिन्दु रहा, परन्तु ऐसा केवल बातचीत के स्तर पर ही होता रहा। संविधान सभा के वाद-विवाद में या योजना आयोग जैसी संस्थाओं में, विधिवत रूप से तैयार की गई नीति परिचर्चा केवल कागजों में ही सिमटी रही और इन्हें कार्यान्वित करने हेतु कारगर उपाय नहीं किए जा सके। श्री अटल बिहारी वाजपेयी के दूरदर्शी नेतृत्व और राजनैतिक कौशल के साथ, हमारा देश ऐतिहासिक सुशासन प्रयासों का साक्षी बना जिनसे जनता के जीवन में समृद्धि आई।

लोक सभा सदस्य के रूप में दस कार्यकाल और राज्य सभा सदस्य के रूप में दो कार्यकाल पूरे करने वाले श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सांसद के रूप में अपनी कार्यावधि के दौरान सुशासन की बारीकियों पर प्रकाश डाला। नेता, प्रतिपक्ष के रूप में उनकी तर्कसंगत दलीलों और रचनात्मक समालोचनाओं में कल्याण-केन्द्रित सुशासन तंत्र के लिए प्रेरित करने का बल था। प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान, उनकी जनोन्मुखी पहलें नये भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित हुई। उनके द्वारा किसानों के जीवन में सुधार लाने के लिए प्रारंभ किए गए किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के द्वारा अवसरंचनात्मक संवर्धन, नदियों को आपस में जोड़ने तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्यक्रम की अवधारणा तैयार करना, सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से शैक्षिक सुधार, पृथक जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन आदि ऐसे कुछ उपाय हैं जिन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रभावित किया। अर्दध-न्यायिक केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना की गई और विद्युत क्षेत्र में वर्षो पुराने विद्युत अधिनियम में संशोधन किया गया ताकि विनियामक रूपरेखा में सुधार किया जा सके।

मई, 1998 में, पोखरण, राजस्थान् में उनकी राष्ट्रीय शासन कार्यसूची के भाग के रूप में किए गए परमाणु परीक्षणों के कारण भारत का नाम परमाणु शक्ति संपन्न देशों में शामिल हो गया। कश्मीर की जटिल समस्या का समाधान करने के लिए वाजपेयी जी के मानवता, शांति और कश्मीरी लोगों के आत्मसम्मान को कायम रखने हेतु प्रसिद्ध सिद्धांत 'इंसानियत, जम्हूरियत और कश्मीरियत' में उनकी लोकप्रिय बौद्धिकता प्रतिबिंबित होती है। विदेश नीति से संबंधित उनके ये विचार कि 'आप मित्र बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं', सभी मंचों पर भागीदारी का निरन्तर स्रोत रहे हैं। मां भारती की रक्षा में अपने प्राणों की आहूति देने वाले हमारे वीर सैनिकों के पार्थिव शव उनके परिवारजनों को सौंपने का निर्णय भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार द्वारा किया गया ताकि मातृभूमि की रक्षा में अपना बलिदान देने वाले शहीदों का अंतिम संस्कार उनके परिवारजनों के द्वारा सम्मानपूर्वक किया जा सके। अटल जी, आपसी सामंजस्य में विश्वास रखने वाले यथार्थवादी राजनेता थे और यह तथ्य इस बात से प्रकट होता है कि वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में से शांतिपूर्ण रूप से क्रमश: छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड नामक तीन नए राज्यों की स्थापना की गई। यह सरकार को जनता के निकट ले जाकर सुशासन स्थापित करने का एक सुविचारित प्रयास था।

वह डॉ. बी.आर.अम्बेडकर के विचारों की भविष्योन्मुखी अंतदृष्टि से अत्यंत प्रभावित थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी और लालकृष्ण आडवाणी जी के प्रयास से ही वी.पी.सिंह सरकार ने भाजपा के समर्थन से डॉ. भीमराव अम्बेडकर को 31 मार्च, 1990 को भारत रत्न से सम्मानित किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की इच्छानुसार दिल्ली स्थित 26 अलीपुर रोड, जहां सिरोही, राजस्थान के महाराजा ने डॉ. अम्बेडकर को केन्द्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा (1951) देने के पश्चात रहने के लिए आमंत्रित किया था, को संग्रहालय के तौर पर विकसित करने की योजना बनाई गई जिससे लोगों को सामाजिक समता के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। डॉ. अम्बेडकर ने इसी स्थान पर अपनी अंतिम सांस ली थी। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा वाजपेयी जी की देखरेख में 14 अक्तूबर, 2003 को निजी संपत्ति के विनिमय विलेख पर हस्ताक्षर किए गए और दिसम्बर, 2003 में विकास कार्य शुरू किया गया। बाद में यूपीए के कार्यकाल के दौरान इस परियोजना को रोक दिया गया। मोदी सरकार ने इसे 100 करोड़ रुपए की लागत पर डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित किया और 13 अप्रैल, 2018 को राष्ट्र को समर्पित किया।

अटल बिहारी वाजपेयी ने 21वीं शताब्दी के प्रारंभ होते ही कई पहलों के साथ सुशासन अभियान को शुरु कर दिया था। अब इस अभियान को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और नए भारत (न्यू इंडिया) को 21वीं शताब्दी का वैश्विक नेता बनाने के लिए इसे तेज गति के साथ आगे बढ़ाया है। डीबीटी, जेएएम ट्रिनिटी, फेसलैस टैक्सेाशन जैसी प्रौद्योगिक युक्तियों और इन्हीं के समान अन्य कार्य योजनाओं को कार्यान्वित करने से विवेकाधीन संसाधनों के कम उपयोग की संभावना बनी है, जिसके फलस्वरूप ऐसी संस्थाओं में लोगों का विश्वास बढ़ा है। जहां किसान क्रेडिट कार्डो का दायरा बढ़ा है वहीं कृषि से संबंधित कार्यकलापों का निगमीकरण हुआ है। भारतमाला, सागरमाला, राष्ट्रीय परिसंपत्ति, नेशनल ऐसेट मोनेटाइनेशन पाइपलाइन, कृषि अवसंरचना निधि और पीएमजीएसवाई चरण-III के विस्तारण के कारण निर्माण क्षेत्र को अत्यधिक बढ़ावा मिला है। अनुच्छेद 370 अर्थात् जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे की समाप्ति के फलस्वरूप जम्मू और कश्मीर में प्रभावी और दक्ष सेवाओं से संबंधित संवितरण कार्य तंत्र (डिलीवरी मकैनिज्म) के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात हुआ है। अब प्रत्येक वर्ग के लोगों को विकास कार्य सूची के दायरे में लाया जा रहा है।

'सरकार की न्यूनतम भूमिका और सुशासन की अधिकतम मात्रा' (मिनिमम गवर्न्मेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस) नामक इस मंत्र से नागरिकों के बीच जीवन की सहज अनुभूति हुई है। संबंधित प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा व्यापारियों, व्यक्तियों और अन्य हितधारकों पर अनुपालन का भार कम करने पर विशेष ध्यान देकर 'मिशन कर्मयोगी' के माध्यम से प्रधानमंत्री गतिशक्ति, प्रगति क्षमता निर्माण जैसी पहलों सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच बेहतर समन्वय के द्वारा सुशासन संबंधी बाधाओं का निराकरण बेहतर सेवा संवितरण सुनिश्चित करेगा। जीएसटी, श्रमिक संहिताओं, दिवाला और वंचन संहिता, नयी शिक्षा नीति, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम किसान और कर संबंधी विवादों के निर्बाध समाधान कार्य कुछ ऐसे अन्य पहलू हैं जिनसे पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन के अन्य आयाम सुदृढ़ हो रहे हैं। यह ऐसे किए गए उपायों का ही प्रमाण है कि आज भारत सहज व्यवसाय संचालन के क्षेत्र में वर्ष 2015 में 145 से 79वें स्थान पर और वर्ष 2020 में 63वें स्थान पर पहुंच गया है। इसी प्रकार भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक में वर्ष 2015 में 81वें स्थान से वर्ष 2021 में 46वें स्थान पर पहुंच गया है। हाल ही में 8 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री परिषद द्वारा केन-बेतवा अंतर संबद्ध परियोजना को मंजूर किए जाने से यह परियोजना अतिशेष जल क्षेत्रों से सूखाग्रस्त और अल्प जल मात्रा वाले क्षेत्रों में जल पहुंचाने वाली पहली प्रमुख केंद्र संचालित परियोजना बन गई है, जिससे अटल जी का देखा सपना साकार हो रहा है।

समाज, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय विकास श्रृंखलाओं से जुड़ा हुआ हैं। इसी प्रकार सुशासन संबंधी सुधारों को कार्यान्वित करने के लिए समानता होना आवश्यक है ताकि सभी हितधारकों के कल्याण के लिए इन रचनात्मक परिवर्तनों को उपयोग में लाया जा सके। मोदी सरकार द्वारा समयबद्ध ढंग से योजनाओं को लागू करना वस्तुत: एक उल्लेखनीय उपलब्धि है जिसके फलस्वरूप अब तक बहुत-सी ऐतिहासिक उपलब्धियां दर्ज हुई हैं। कहा जाता है कि सुधार के लिए हमेशा गुंजाइश रहती है, इसलिए बहुत-से महत्वपूर्ण सुधार कार्य अनवरत रूप से किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक साथ चुनाव कराने, एकल चुनाव पंजिबनाने और राष्ट् के सर्वाधिक हित में बहुत-से मंचों पर अखिल भारतीय न्यायिक सुधारों के प्रति अपनी चिंता अभिव्यक्त की है। सुधार प्रक्रियों पर तेजी से अमल करने के लिए सभी संबंधित हितधारकों के बीच संघीय और राजनीतिक स्तरों पर उचित परामर्श किए जा रहे हैं। अच्छे् सुशासन से अभिप्रेत, सुसंस्थापित संवैधानिक कार्ययोजना के माध्यम से लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में कदम उठाते हुए उनकी अपरिहार्य रूप में सेवा करने से है। अटल जी का दृष्टिकोण, नेतृत्व, मार्गदर्शन और उनकी अमूल्य अंतर्दृष्टि वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए हमेशा ही प्रेरणास्रोत बनी रहेगी। चूंकि, राष्ट्र आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान सुशासन दिवस मना रहा है, इसलिए आवश्यक है कि हम न्यू इंडिया का निर्माण करने के लिए 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' की भावना से काम करने के लिए अपना आत्मविश्लेषण करते हुए शपथ लें।

काशी विश्वनाथ धाम-हमारी जींवत विरासत को सम्मान

अनुराग सिंह ठाकुर
केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल और सूचना व प्रसारण मंत्री

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन किया। यह अनूठी परियोजना, काशी जैसे सभ्यता के प्रतीक शहर और ऐतिहासिक काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए सर्वथा उपयुक्त है। काशी के महत्व और प्राचीनता के बारे में मार्क ट्वेन ने लिखा था, 'बनारस इतिहास से भी पुराना है, परंपरा से भी पुराना है, पौराणिक कथाओं से भी पुराना है और इन सभी को मिलाने से जितनी प्राचीनता हो सकती है, यह शहर उससे भी दोगुना प्राचीन है।'

परियोजना के उद्घाटन के साथ, प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के सबसे प्राचीन जीवित शहरों में से एक और हिंदू धर्म तथा सदियों पुरानी हमारी सभ्यता के केंद्र, काशी या वाराणसी को दुनिया को फिर से समर्पित किया। प्राचीनता और निरंतरता का अद्भुत मिश्रण, काशी पूरी मानवता की धरोहर है।

इसे दुनिया का सबसे प्राचीन व एक ऐसा शहर माना जाता है, जो सदियों से लोगों का निवास-स्थान रहा है। जहां दुनिया के अन्य प्राचीन शहर साम्राज्यवादी और औपनिवेशिक हमलों में ध्वस्त हो गए, वहीं काशी अपने विशिष्ट उत्साह के साथ गतिमान है। यह शहर को वास्तव में महत्वपूर्ण और अद्वितीय बनाता है। अपनी निरंतरता के माध्यम से, यह शहर बर्बर आक्रमणों और हमलों के बावजूद अपनी सांस्कृतिक, कलात्मक और शैक्षिक पहचान को बनाए रखने के लिए अपनी दृढ़ सहनशीलता का परिचय देता है।

काशी विश्वनाथ धाम, इस शहर पर हुए अत्याचार से भरे अतीत से ऊपर उठने की एक पवित्र प्रतिज्ञा को दर्शाता है। दूसरे शब्दों में, यह इस भूमि की सदियों पुरानी आध्यात्मिक, शैक्षिक और रचनात्मक विरासत को फिर से जीवंत करने का एक विनम्र प्रयास है। इस धाम के रूप में इतिहास ने नया मोड़ लिया है। इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि एक हजार साल के अन्याय को, बिना किसी विनाश, लूटपाट या बदले की भावना के, समाप्त करते हुए पहले जैसी स्थिति प्राप्त की गयी है। इसे केवल निर्माण और सृजन के माध्यम से हासिल किया गया है।

काशी को युगों से मुक्ति की नगरी के रूप में जाना जाता रहा है। हर जगह से लोग मुक्ति की खोज में काशी की ओर खिंचे चले आते हैं। हालांकि यह परियोजना स्वयं काशी की मुक्ति का उत्सव मनाने का एक प्रयास है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इस दृष्टिकोण और प्रयासों ने काशी विश्वनाथ मंदिर के सदियों पुराने गौरव को पुन: स्थापित किया है।

काशी विश्वनाथ धाम संपूर्ण मानवता के लिए एक परियोजना है क्योंकि यह सभ्यता की निरंतरता का एक उत्सव है। इस दृष्टि से, यह पूरी दुनिया के लिए एक परियोजना है। यह हिंदू देवालय भगवान ब्रह्मा- ब्रह्मांड के रचयिता, भगवान विष्णु- ब्रह्मांड के रक्षक और भगवान शिव - ब्रह्मांड के मुक्तिदाता- की पवित्र त्रिमूर्ति को मान्यता प्रदान करता है। काशी अत्यधिक श्रद्धा जगाती है क्योंकि यह भगवान शिव के विभिन्न निवासों में से एक है। यही काशी का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है।

इस वर्ष संविधान दिवस के अवसर पर, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था, 'भारत और दुनिया के कई देशों के लिए कई पीढ़ियों तक उपनिवेशवाद की बेड़ियों में रहना एक मजबूरी थी। भारत की आजादी के बाद से, पूरी दुनिया में एक उत्तर-औपनिवेशिक काल शुरू हुआ और कई देश आजाद हुए। आज दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो किसी दूसरे देश के उपनिवेश के रूप में मौजूद हो। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि औपनिवेशिक मानसिकता का अस्तित्व समाप्त हो गया है।'

इसलिए, कई पीढ़ियों तक उपनिवेशवाद झेलने वाली मानवता के लिए यह आवश्यक है कि वह स्वयं को उपनिवेश से मुक्त करे, आजाद हो और फिर से आगे बढ़े।

कई अन्य बातों के अलावा, ऐतिहासिक रूप से लूट और विध्वंस उपनिवेशवाद के मुख्य उपकरण और उद्देश्य, साधन एवं साध्य रहे हैं। स्वाभाविक रूप से, धन, ज्ञान और पुरातत्व के खजाने से लैस सभ्यताएं इस किस्म के बर्बर जमाखोरों के लिए प्रमुख आकर्षण थीं।

आइए, एक फिर काशी की ओर लौटें। यह पौराणिक प्राचीन शहर लगातार लूटपाट का शिकार रहा है। यहां हुए विध्वंस और विनाश, इस बात के पर्याप्त संकेत देते हैं कि एक समय यह कितना शानदार शहर रहा होगा। यह तथ्य दुनिया भर के संग्रहालयों और निजी संग्रहों में बिखरे पड़े काशी के गौरवशाली पुरावशेषों के नमूनों से भी प्रमाणित होता है।

सामान्य रूप से काशी शहर और विशेष रूप से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर को अतीत में कई बार ध्वस्त किया गया और इनका पुनर्निर्माण हुआ। प्रारंभ में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर को घुरिद तुर्क सुल्तान कुतुब-उद-दीन ऐबक ने नष्ट किया था और फिर बाद में गुजरात के एक व्यापारी ने इसे पुनर्निर्मित किया था। इस मंदिर के विध्वंस और पुनर्निर्माण की कहानी वर्ष 1780 तक जारी रही, जब एक किंवदंती के अनुसार, भगवान शिव महान मराठा रानी अहिल्याबाई होल्कर के सपने में आए एवं वह भगवान शिव की परम भक्त बन गई और फिर उन्होंने इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया। एक अन्य किंवदंती के अनुसार, इस शहर पर किए गए हमले ने ही महान छत्रपति शिवाजी महाराज को तलवार उठाने के लिए प्रेरित किया था। यह कहा जाता है कि औरंगजेब द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर के विध्वंस ने शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई को इतना क्रोधित कर दिया था कि उन्होंने उन्हें मुगल के नियंत्रण वाले एक किले सिंहगढ़ पर कब्जा करने की चुनौती दे डाली। इसके बाद क्या हुआ वह सर्वविदित है।

मंदिर परिसर का पुनर्निर्माण न केवल औपनिवेशिक प्रभाव से बाहर निकलने की दिशा में एक और अहम कदम है, बल्कि यह बर्बरता पर सभ्यता की प्रधानता, ज्ञान के केंद्र की पुनर्स्थापना और क्रूरता के स्थान पर श्रद्धा का भाव जागृत होने का भी ठोस प्रतीक है। यह परियोजना पूर्ण सामंजस्य सुनिश्चित करते हुए रचनात्मक दृष्टिकोण के जरिए इन प्रशंसनीय लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक अभिनव प्रयास है। यह पूरी मानवता के लिए गहन चिंतन-मनन करने और इसके साथ ही, यदि संभव हो सके, तो अनुसरण करने का भी एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मेरी मंगल कामना है कि हमारी काशी ठीक इसी तरह से आगे भी निरंतर फलती-फूलती रहे एवं समृद्ध होती रहे और इसके साथ ही भगवान शिव हम सभी को अपनी दिव्यता एवं महिमा प्रदान करें।

प्रदेश में सहकारिता के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन किया जा रहा हैः सुरेश भारद्वाज

शिमला/शैल। सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम शिमला द्वारा सहकारिता विभाग के साथ सहभागिता में सहकारी विकास में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन तथा योगदान के लिए क्षेत्रीय सहकारी

उत्कृष्ट और मैरिट पुरस्कार-2021 तथा सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि देश में सहकारिता को आरम्भ करने वाले हिमाचल प्रदेश में सहकारी क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किया जा रहा है।

सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश में जिस प्रकार सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है उससे यह प्रदर्शित होता है कि प्रदेश में आम जनता के कल्याण व उत्थान को सदैव प्राथमिकता दी जाती है। उन्होंने इस अवसर पर उत्कृष्ट और मैरिट पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार सराहनीय प्रदर्शन करने वालों को सदैव प्रोत्साहित करती रही है तथा भविष्य में भी ऐसे लोगों को उल्लेखनीय कार्य के लिए बढ़ावा दिया जाएगा।

इससे पूर्व सुरेश भारद्वाज ने राज्य की चयनित प्राथमिक समिति दि शिखर हथकरघा व हस्तशिल्प बुनकर सहकारी सभा रामपुर तथा दि पठियार कृषि सहकारी सभा नगरोटा बगवां को सहकारी उत्कृष्ठता पुरस्कार और दी भुट्टी बुनकर सहकारी सभा भुन्तर तथा दि धार छटोत्रयां कृषि सहकारी सभा जयसिंहपुर को सहकारी मैरिट पुरस्कार प्रदान किया।

सहकारिता मंत्री ने कहा कि सहकारी क्षेत्र में किसानों तथा बागवानों की आय को बढ़ाने तथा उनके उत्पादन को उचित विपणन व अन्य सुविधाएं प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने सहकारिता विभाग के अधिकारियों को लोगों को सहकारी योजनाओं के बारे जागरूक कर उन्हें लाभान्वित करने के निर्देश दिए।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम शिमला के क्षेत्रीय निदेशक राकेश वर्मा ने इस अवसर पर सहकारिता मंत्री का स्वागत किया।

सचिव सहकारिता अक्षय सूद ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सदैव सहकारिता को प्राथमिकता प्रदान की है तथा सहकारी सभाओं के माध्यम से प्रदेश के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है। उन्होंने सहकारी सभाओं में अधिक से अधिक युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने पर बल दिया।

पंजीयक राज्य सहकारी सभाएं राजेश शर्मा ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

अरावली क्लस्टर आधारित व्यापार संगठन (सीबीबीओ) के निदेशक डॉ. यशपाल शर्मा ने प्रदेश में किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) के योगदान पर प्रस्तुति प्रस्तुत की।

इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक सरवन मान्टा, सभी जिलों के सहायक पंजीयक, चयनित सहकारी सभाओं के प्रतिनिधि, सीबीबीओ व एफपीओ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व प्रधान, सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों सहित अन्य गणमान्य भी उपस्थित थे।

राज्यपाल ने आदर्श नशामुक्ति एवं पुनर्वास केन्द्र का दौरा किया

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने मण्डी में

आदर्श नशामुक्ति एवं पुनर्वास केन्द्र का दौरा किया। इस केन्द्र का संचालन क्षेत्रीय अस्पताल मण्डी द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के तत्वावधान में किया जा रहा है। उन्होंने केन्द्र की विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा की और वहां प्रदान की जा रही सुविधाओं का जायजा लिया।

राज्यपाल ने प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक भी की और अधिकारियों को इस केन्द्र में टेनिस, चैस, योगा और मैडिटेशन इत्यादि इन्डोर सुविधाएं उपलब्ध करवाने को कहा।

उन्होंने उपचाराधीन लोगों के पुनर्वास के लिए एक योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. देविन्दर ने केन्द्र की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी।

इस अवसर पर उपायुक्त मण्डी अरिन्दम चौधरी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

सभी पंचायतों में चरणबद तरीके से खेल मैदान किए जाएंगे विकसित:कंवर

शिमला/शैल। राज्य की सभी पंचायतों में चरणबद तरीके से खेल मैदान विकसित किए जाएंगे ताकि ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। यह उदगार ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र

कंवर ने हरिपुर में संसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ करने के उपरांत खिलाड़ियों को सम्बोधित करते हुए व्यक्त किए।

उन्होंने कहा कि सांसद खेल महाकुंभ में क्रिकेट, कबड्डी, बास्केटबॉल, वालीबॉल, फुटबाल, कुश्ती और एथलेटिक्स स्पर्धाओं के लिए लगभग 2100 टीमों का पंजीकरण किया गया है। इस बार खेल महाकुंभ में लड़कियां भी बड़ी संख्या में भाग ले रही हैं। इन स्पर्धाओं के विजेताओं को लगभग 50 लाख रुपये के ईनाम दिए जाएंगे तथा हजारों प्रतिभागियों को टी-शर्ट्स व अन्य सामग्री भी दी जाएगी। महाकुंभ के दौरान प्रतिभागियों को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में सराहनीय प्रदर्शन करने वाले प्रतिभाशाली खिलाडियों को आगे बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि सांसद खेल महाकुंभ की शुरुआत करके केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है। अब देश के अन्य राज्यों के सांसद भी अनुराग सिंह ठाकुर का अनुसरण करते हुए अपने-अपने संसदीय क्षेत्रों में इस प्रकार के आयोजन करवाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के हजारों युवाओं के जुड़ने से इस खेल महाकुंभ के बहुत ही उत्साहजनक परिणाम सामने आएंगे तथा आने वाले समय में यहां से कई ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी निकलेंगे जोकि राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि इन्हीं प्रतिभाशाली खिलाडियों में से ओलंपिक मैडल विजेता भी निकलेंगे। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई के साथ-साथ खेलों का भी अपना अलग ही महत्व है। इससे बच्चों-युवाओं में अनुशासन एवं खेल की भावना विकसित होती है तथा देश आगे बढ़ता है।

कंवर ने कहा कि केंद्रीय मंत्री और एक युवा नेता के रूप में अनुराग सिंह ठाकुर ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है तथा वे देश भर में हिमाचल प्रदेश का गौरव बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनुराग सिंह ठाकुर स्वयं भी एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ-साथ खेल मंत्रालय को भी सशक्त एवं दूरदर्शी नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं।

समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए पूर्व मंत्री रविंद्र रवि ने कहा कि खेल महाकुंभ से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने तथा जीवन में आगे बढ़ने का बेहतरीन अवसर मिल रहा है। रविंद्र रवि ने सभी खिलाडियों से अनुशासन एवं उच्च खेल भावना के साथ इस आयोजन में भाग लेने की अपील भी की।

इस अवसर पर जिला भाजपा अध्यक्ष संजीव शर्मा, मंडल अध्यक्ष निर्मल, पार्टी के अन्य पदाधिकारी, खेल महाकुंभ के सयोजक टीपी चोपड़ा, अनुपम लखनपाल एसडीएम धनवीर ठाकुर और अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में ओमीक्रॉन से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने प्रदेश के विभिन्न उपायुक्तों के साथ राज्य में कोविड के नए वेरिएंट ओमीक्रॉन से निपटने की तैयारियों की वर्चुअल माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक की

अध्यक्षता की।

मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को अपने संबंधित जिलों में कोविड-19 से संबंधित उचित प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नए साल को मनाने के लिए देश के विभिन्न भागों से प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इसलिए पर्यटकों द्वारा कोविड अनुरूप व्यवहार की अनुपालना सुनिश्चित की जानी चाहिए।

जय राम ठाकुर ने पर्यटकों की अधिक संख्या वाले जिलों के उपायुक्तों को कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने टेस्टिंग बढ़ाने और जिन क्षेत्रों में कोरोना के मामले सामने आए हैं वहां माइक्रोकंटेमेंट जोन बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने उपायुक्तों को अन्य राज्यों से आने वाले लोगों के लिए टीकाकरण शिविर आयोजित करने के लिए कहा ताकि इस संक्रमण के प्रसार को रोका जा सके।

मुख्यमंत्री ने पी.एस.ए. संयंत्रों के संचालन और अस्पतालों में मरीजों के लिए समुचित व्यवस्था के साथ मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विदेशों से आने वाले लोगों की कड़ी निगरानी पर भी बल दिया और यदि कोई व्यक्ति कोविड पॉजिटिव आता है तो ऐसे व्यक्तियों की कान्टेक्ट ट्रेसिंग पर विशेष बल देने को कहा।

उन्होंने कहा कि लोगों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और प्रदेश के लोगों को कोविड के नए वेरिएंट से सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए।

इस अवसर पर मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने भी अपने बहुमूल्य सुझाव व्यक्त किए। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया।

अतिरिक्त मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव जे.सी. शर्मा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक हेमराज बेरवा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।

योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश के विकास को नई दिशा मिली: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने चार वर्ष के कार्यकाल के दौरान समाज के हर वर्ग और हर क्षेत्र का विकास सुनिश्चित किया है। इस अवधि में सरकार ने अनेक नई योजनाएं आरम्भ की हैं, जिससे विकास के एक नए युग का सूत्रपात हुआ है। वर्तमान राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश को हिमाचल की संस्कृति के अनुरूप आगे बढ़ाया है।

मुख्यमंत्री ने यह बात निजी टीवी चैनल खबरें अभी तक द्वारा आयोजित साइनिंग हिमाचल कॉन्क्लेव-2021 के दौरान कही। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के सक्रिय सहयोग और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आशीर्वाद से प्रदेश में विकास को तीव्र गति मिली है। कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावशाली क्रियान्वयन से प्रदेशवासियों के जीवन में सकारात्मक सामाजिक-आर्थिक बदलाव देखने को मिला है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन-1100, मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना, मुख्यमंत्री हिमाचल हेल्थकेयर योजना-हिमकेयर, मुख्यमंत्री सहारा योजना, प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान, मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना सहित अनेक महत्वकांक्षी योजनाएं आरम्भ की हैं।

उन्होंने कहा कि बहुत से क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश के सूचकांक देश के कई बड़े राज्यों से आगे हैं। हिमाचल कोविड टीकाकरण अभियान में लक्षित पात्र आबादी को पहली व दूसरी डोज लगवाने में शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने वाला देश में पहला राज्य है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों के सूचकांक और डैशबोर्ड 2020-21 में प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है।

उन्होंने कहा कि कोविड-19 के प्रभाव के बावजूद हिमाचल प्रदेश में विकास को रफ्तार देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए, जिनके आशातीत परिणाम सामने आए हैं। इंडिया टुडे द्वारा वर्ष 2021 में जारी मोस्ट इम्प्रूवड बिग स्टेट इन हेल्थ सर्वे में हिमाचल प्रदेश को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों के विकास में मॉडल राज्य के रूप में उभरे हिमाचल प्रदेश ने अपनी अलग पहचान बनाई है।

शैक्षणिक भ्रमण पर हिमाचल आये गोवा के विद्यार्थियों ने राज्यपाल से भेंट की

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से राज भवन में शैक्षणिक भ्रमण पर हिमाचल आए गोवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, पंजिम के विद्यार्थियों ने भेंट की।

इस अवसर पर राज्यपाल ने विद्यार्थियों को हिमाचल प्रदेश के इतिहास, भौगोलिक स्थिति और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हिमाचल का वातावरण शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक है। उन्होंने विद्यार्थियों को हिमाचल प्रदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों और विभिन्न विश्वविद्यालयों की जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल शिक्षा का हब है और यहां साक्षरता दर भी बहुत अच्छी है।

राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 से बचाव उपायों व दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। यह देश का ऐसा प्रथम राज्य है जहां शत-प्रतिशत पात्र आबादी का कोविड से सुरक्षा के लिए टीकाकरण किया जा चुका है। विद्यार्थियों ने राज्यपाल के साथ शैक्षणिक भ्रमण के दौरान अपने विभिन्न अनुभव साझा किए।

मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत ज्ञान केन्द्र का शुभारम्भ किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयन्ती के अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री के गांव प्रीणी और जिला कुल्लू के नग्गर, कुल्लू और बंजार विकास खण्डों की दस ग्राम पंचायतों में जिला प्रशासन की पहल ग्राम पंचायत ज्ञान केन्द्र का शुभारम्भ किया।

ग्राम पंचायत ग्राम केन्द्रों के प्रधानों से वर्चुअल माध्यम से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन की यह सराहनीय पहल है, जिससे इन पंचायतों के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को न केवल घर के निकट चौबीस घंटे पुस्तकालय बल्कि इंटरनेट और वाई-फाई की सुविधा भी प्राप्त होगी।

जय राम ठाकुर ने कहा कि यह पहल अटल बिहारी वाजपेयी की जयन्ती के अवसर पर की गई है, इसलिए पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान स्वरूप इन केन्द्रों का नाम अटल ज्ञान केन्द्र होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस पहल को सशक्त करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री ने ज्ञान केन्द्रों को पुस्तकें प्रदान करने के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने लोगों से भी इन केन्द्रों के लिए पुस्तकें दान देने का आग्रह किया। उन्होंने जिला कुल्लू और प्रदेश की अन्य पंचायतों से भी इस पहल को अपनाने का आग्रह किया।

इस अवसर पर प्रीणी पंचायत की प्रधान कल्पना आचार्य ने शॉल व टॉपी भेंट कर मुख्यमंत्री का स्वागत किया।

कुल्लू के उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने मुख्यमंत्री को जिला प्रशासन की इस पहल के बारे में जानकारी प्रदान की।

शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर, बंजार के विधायक सुरेन्द्र शौरी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

शिमला से चंडीगढ़ हवाई अड्डा के लिए वोल्वो बस सेवा शुरू

शिमला/शैल। परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने शिमला में अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा चंडीगढ़ के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम की वोल्वो बस सेवा का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर परिवहन मंत्री ने कहा कि यह बस सेवा शिमला से चंडीगढ़ हवाई अड्डा और अन्तरराज्यीय बस अड्डा चंडीगढ़ जाने वाले यात्रियों के लिए सुविधाजनक होगी। इसमें प्रति शिमला से चंडीगढ़ प्रति व्यक्ति किराया 450 रुपये होगा और बस का प्रस्थान दोपहर 12:45 बजे होगा।

उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए शिमला शहर के दो स्थानों न्यू शिमला व संजौली से सम्पर्क बस सेवा भी चलायी गयी है, जो आईएसबीटी टुटीकंडी तक हवाई यात्रा टिकट वाले यात्रियों को नि:शुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध करवायेगी। इस बस सेवा का अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा से प्रस्थान समय सायं 7:30 बजे होगा तथा यह बस सेवा रात्रि 11:00 बजे शिमला पहुंचेगी। इस बस सेवा के यात्रियों को अपने गंतव्य के लिए भी नि:शुल्क बस सेवा सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।

परिवहन मंत्री ने अन्य महत्वपूर्ण स्थानों के लिए भी हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस सेवा आरम्भ करने के लिए अधिकारियों को योजना बनाने के निर्देश दिये।

इस अवसर पर उन्होंने शिमला से जम्मू-कटड़ा वाया हमीरपुर, कांगड़ा, पठानकोट रूट पर एचआरटीसी की वोल्वो बस सेवा 7 जनवरी, 2022 से आरम्भ करने की घोषणा की। इस बस सेवा में यात्रियों को किराये में 35 प्रतिशत रियायत दी जाएगी, शिमला से कटड़ा तक प्रति व्यक्ति किराया 1475 रुपये होगा।

इस अवसर पर हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रबन्ध निदेशक संदीप कुमार, वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।

राज्य सलाहकार बोर्ड प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग की प्रथम बैठक आयोजित

शिमला/शैल। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने आयोजित राज्य सलाहकार बोर्ड प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की।

इस अवसर पर डॉ. राजीव सैजल ने कहा कि राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में वर्ष 2023-24 तक 400 आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों को स्तरोन्नत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके तहत लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए योग शिक्षक तैनात किए जाएंगे। आयुष विभाग के 135 आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों में अंशकालिक रूप से आउटसोर्स आधार पर योग प्रशिक्षक तैनात करने का निर्णय लिया गया है।

उन्होंने कहा कि आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों को योग में प्रशिक्षण के लिए प्रस्ताव तैयार करने, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र ओयल जिला ऊना को सुदृढ़ करने तथा बोर्ड की बैठक त्रैमासिक आधार पर आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।

गैर सरकारी सदस्य श्रीनिवास मूर्ति ने योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के उत्थान के लिए योग भारती संगठन द्वारा किए जा रहे कार्यों, लक्ष्मी शर्मा ने भारत स्वाभिमान के अन्तर्गत चलाई जा रही गतिविधियों तथा आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की प्रतिनिधि मीनाक्षी संघैक ने संस्था द्वारा योग के क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों की जानकारी प्रदान की।

बैठक में उपाध्यक्ष राज्य सलाहकार बोर्ड प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग व अतिरिक्त मुख्य सचिव निशा सिंह, निदेशक आयुष विनय सिंह, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली के प्रतिनिधि डॉ. अर्पित दुबे, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान पुणे के प्रतिनिधि डॉ. डी सथयनाथ, शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि प्रो. जी.डी. शर्मा, राज्य सलाहकार बोर्ड के सदस्यों एवं अधिकारियों ने भाग लिया।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

सरकार पर लगे हिमाचल बेचने के आरोप कांग्रेस ने दिया राज्यपाल को ज्ञापन

- उद्योग लगाने के लिए तीन वर्ष तक सरकार से किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं
- कर्ज लेकर संपत्ति बनाये और दोहन के लिए प्राइवेट सैक्टर को दे दे तो...
- क्या यह सब धारा 118 पर पिछले दरवाजे से हमला नहीं

शिमला/शैल। जयराम सरकार ने सत्ता में चार साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री के गृह जिला मण्डी में प्रधानमंत्री को बुलाकर जहां एक बड़ा जश्न मनाया है वहीं पर विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार पर हिमाचल बेचने के आरोप लगाते सरकार की नाकामियों पर एक सात पन्नों का ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा है। ज्ञापन में राज्यपाल से स्थिति का कड़ा संज्ञान लेते हुए तुरंत हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। हिमाचल में गैर कृषकों को और गैर हिमाचलीयों पर सरकार की पूर्व अनुमति के बिना जमीन खरीद पर प्रतिबंध है। ऐसे में जब भी किसी भी तरह का कोई उद्योग लगाने का प्रस्ताव सरकार के पास आता है तब ऐसे उद्योग पर यह नियम लागू होते हैं। यही नहीं जमीन खरीद की पूरी अनुमति के अतिरिक्त और भी कई विभागों से पूर्व अनुमतियां लेनी पड़ती हैं। इसमें प्रायः कई बार नियमों की अनदेखी होने के आरोप भी लगते आये हैं । शांता, वीरभद्र और प्रेम कुमार धूमल सभी की सरकारों पर यह आरोप लगे हैं। इन आरोपों की जांच के लिए एस एस सिद्धू जस्टिस रूप सिंह ठाकुर और जस्टिस डी पी सूद की अध्यक्षता में जांच कमेटीयां भी बनी है। इन कमेटियों की रिपोर्ट भी आयी है। लेकिन यह कभी सामने नहीं आया है कि इन पर कार्रवाई क्या हुई है।

अब जयराम सरकार भी इस आरोप से बच नहीं पायी है। इस सरकार पर इस की नीति को लेकर ही आरोपों की स्थिति बन गयी है। क्योंकि इस सरकार ने उद्योगों को यह छूट दे रखी है कि उन्हें उद्योग स्थापित करने के लिए पहले तीन वर्षों में किसी भी तरह की कोई भी पूर्व अनुमति या एनओसी किसी भी विभाग से लेने की आवश्यकता नहीं होगी। स्वभाविक है कि जब तीन वर्ष तक किसी भी तरह की पूर्व अनुमति की आवश्यकता ही नहीं होगी तो इससे एक अलग तरह का प्रशासनिक वातावरण प्रदेश में स्थापित हो जायेगा। जिसको जहां पर भी जिस भी तरह से जमीन मिल पायेगी वह ले ली जायेगी। जमीन बेचने वाला जमीन बेचकर स्वयं भूमिहीन तो नहीं होने जा रहा है इसका ध्यान रखने का कोई प्रावधान ही नहीं है। प्रस्तावित उद्योग पर्यावरण मानकों की कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं इसका भी उद्योग स्थापित होने से पहले कोई संज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं रखी गयी है। जब उद्योग लगाने से पहले सरकार से कोई वास्ता ही नहीं रखा गया है तो निश्चित रूप से तीन वर्षों में उद्योग लग भी जायेगा। आप्रेशन में भी आ जायेगा और यह भी पता चल जायेगा कि संबंधित उद्योग का भविष्य क्या होगा। तीन वर्ष बाद इस पर सरकार के कायदे कानून लागू होंगे। तब भ्रष्टाचार के लिये अधिकारिक रूप से स्थान मिल जायेगा। उद्योग के अनुसार सारे मानक गढ़े जायेंगे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि तब किस तरह की कार्य संस्कृति प्रदेश में आ जायेगी। सरकार की इस उद्योग नीति को लेकर आज तक प्रदेश में कोई सार्वजनिक बहस नहीं हो पायी है। माना जा रहा है कि तब उद्योग स्वयं ही एक पत्र देकर यह घोषित करेंगे कि उन्होंने किसी भी तरह के नियमों की कोई अनदेखी नहीं की है और प्रशासन इसे स्वीकार कर लेगा।

अभी जिस तरह से पर्यटन के नाम पर जंजैहली, बड़ा गांव और क्यारी घाट में एशियन विकास बैंक से ऋण लेकर कन्वैन्शन सेंटर स्थापित किए गये और उन्हें आप्रेशनल होने से पहले ही प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया गया है उससे कांग्रेस के इस हिमाचल बेचने के आरोप को स्वतः ही अधिमान मिल जाता है। क्योंकि स्वयं कर्ज लेकर संपत्तियां बनाओ और फिर उसे दोहन के लिए निजी क्षेत्र को सौंप दो तो निश्चित रूप से सरकार की नीयत और नीति दोनों पर ही सवाल उठेंगे। क्योंकि सरकार की इस तरह की नीति से भू- सुधार अधिनियम की धारा 118 के औचित्य पर भी सवाल उठेंगे। सरकार जब उद्योगों को सारे कायदे कानूनों से छूट दे देगी और स्वयं कर्ज लेकर प्राइवेट सैक्टर को संपत्तियां सौंपेगी तो इसे पिछले दरवाजे से धारा 118 पर हमला माना जायेगा।

क्या परिवार रजिस्टर की नकल में हरिजन शब्द लिखा जाना आपत्तिजनक है

शिमला/शैल। आने वाले चुनावी में प्रदेश के तीसरे दलों की भूमिका क्या होगी इसको लेकर सवाल उठने शुरू हो गये हैं। यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि दलित समाज के कुछ संगठनों ने पिछले दिनों एक आयोजन करके यह मुद्दा उठाया था कि उनके लिए आवंटित बजट का सरकार 7 प्रतिशत भी खर्च नहीं कर रही है। इस आशय का एक ज्ञापन भी प्रदेश के राज्यपाल को सौंपा गया था। इसमें राज्यपाल से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया गया था। इसी दौरान कुछ स्वर्ण संगठनों ने जातिगत आरक्षण समाप्त करके आर्थिक आधार पर करने तथा इसके लिये एक स्वर्ण आयोग गठित करने की मांग की। इसके लिये आंदोलन हरिद्वार तक की पदयात्रा और शिमला में एट्रोसिटी एक्ट को लेकर एक शव यात्रा तक आयोजित की गयी। स्वर्ण समाज के इस आंदोलन को देखकर सरकार ने सामान्य वर्ग आयोग का गठन भी कर दिया।

सामान्य वर्ग के लिए आयोग गठित कर दिये जाने के बाद दलित समाज ने एट्रोसिटी एक्ट की शव यात्रा को राष्ट्रद्रोह करार देने के लिए बसपा के माध्यम से राज्यपाल

भाटिया के पत्र से उठा सवाल

को ज्ञापन दिया। अब संत रविदास धर्म सभा के प्रदेशाध्यक्ष कर्मचन्द भाटिया ने राज्यपाल को पत्र लिखकर मांग की है कि भू अभिलेख के शजरा नसब में जाति, गोत्र, समुदाय, बिरादरी और वंशावली दर्ज होती है। इस अभिलेख कि जब नकल लेने के लिये जा रहे हैं तब उनकी परिवार नकल प्रति पर अनुसूचित जाति समुदाय के कॉलम में हरिजन शब्द लिखा जा रहा है। सामान्य वर्ग के लोगों के लिए स्वर्ण शब्द लिख रहे हैं। हरिजन और स्वर्ण शब्दों को भूलेख में अंकित करना संविधान की भावना तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अवमानना माना जा रहा है। राज्यपाल से अनुरोध किया गया है कि वह इसे बंद करवाये।

प्रदेश में इस समय दलितों की संख्या करीब 30% होने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में जिस तरह से इस समाज के लिये आवंटित बजट भी पूरा नहीं खर्च किया जा रहा है और ऊपर से अभिलेखों की नकल लेने में हरिजन शब्द दर्ज किया जा रहा है उससे इस समाज के भीतर एक रोष अवश्य पनपता जा रहा है। यह रोष यदि आने वाले समय में एक अलग राजनीतिक राह अपना लेता है तो इसका प्रदेश राजनीतिक समीकरणों पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा यह तय है।

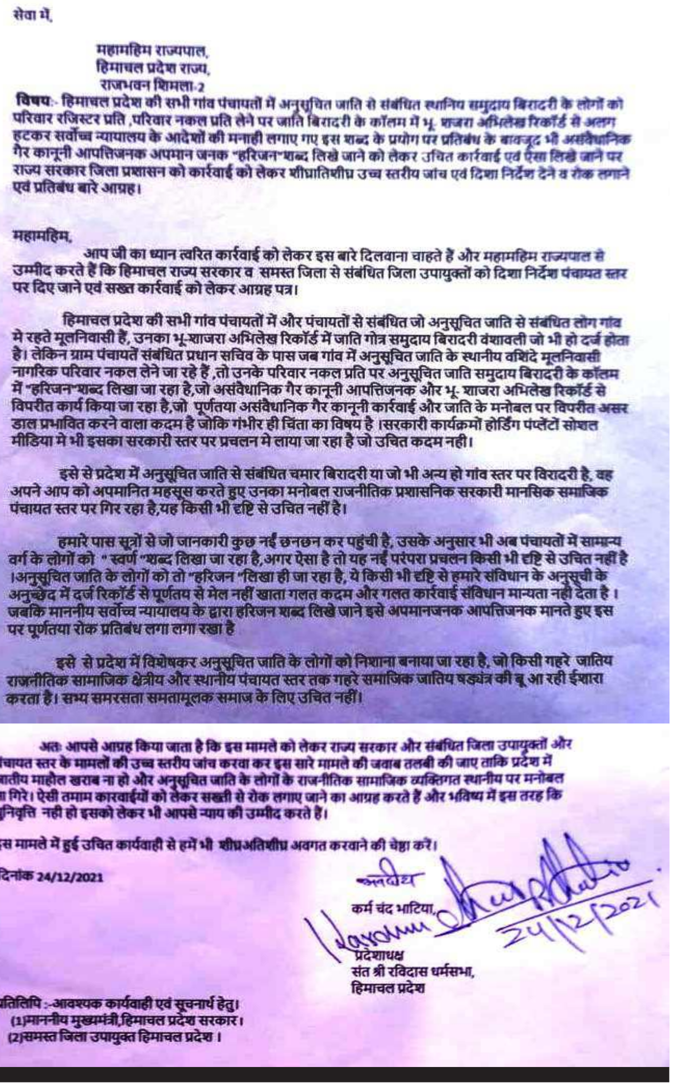
सेवा में,

महामहिम राज्यपाल,
हिमाचल प्रदेश राज्य,
राजभवन शिमला-2

विषय:- हिमाचल प्रदेश की सभी गांव पंचायतों में अनुसूचित जाति से संबंधित स्थानिय समुदाय बिरादरी के लोगों को परिवार रजिस्टर प्रति ,परिवार नकल प्रति लेने पर जाति बिरादरी के कॉलम में भू- शजरा अभिलेख रिकॉर्ड से अलग हटकर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की मनाही लगाए गए इस शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध के बावजूद भी असंवैधानिक गैर कानूनी आपत्तिजनक अपमान जनक "हरिजन"शब्द लिखे जाने को लेकर उचित कार्रवाई एवं ऐसा लिखे जाने पर राज्य सरकार जिला प्रशासन को कार्रवाई को लेकर शीघ्रातिशीघ्र उच्च स्तरीय जांच एवं दिशा निर्देश देने व रोक लगाने एवं प्रतिबंध बारे आग्रह।

महामहिम,
आप जी का ध्यान त्वरित कार्रवाई को लेकर इस बारे दिलवाना चाहते हैं और महामहिम राज्यपाल से उम्मीद करते हैं कि हिमाचल राज्य सरकार व समस्त जिला से संबंधित जिला उपायुक्तों को दिशा निर्देश पंचायत स्तर पर दिए जाने एवं सख्त कार्रवाई को लेकर आग्रह पत्र।

हिमाचल प्रदेश की सभी गांव पंचायतों में और पंचायतों से संबंधित जो अनुसूचित जाति से संबंधित लोग गांव मे रहते मूलनिवासी हैं, उनका भू-शाजरा अभिलेख रिकॉर्ड में जाति गोत्र समुदाय बिरादरी वंशावली जो भी हो दर्ज होता है। लेकिन ग्राम पंचायतें संबंधित प्रधान सचिव के पास जब गांव में अनुसूचित जाति के स्थानीय वशिंदे मूलनिवासी नागरिक परिवार नकल लेने जा रहे हैं ,तो उनके परिवार नकल प्रति पर अनुसूचित जाति समुदाय बिरादरी के कॉलम में "हरिजन"शब्द लिखा जा रहा है,जो असंवैधानिक गैर कानूनी आपत्तिजनक और भू- शाजरा अभिलेख रिकॉर्ड से विपरीत कार्य किया जा रहा है,जो पूर्णतया असंवैधानिक गैर कानूनी कार्रवाई और जाति के मनोबल पर विपरीत असर डाल प्रभावित करने वाला कदम है जोकि गंभीर ही चिंता का विषय है ।सरकारी कार्यक्रमों होर्डिंग पंप्लेटों सोशल मीडिया मे भी इसका सरकारी स्तर पर प्रचलन मे लाया जा रहा है जो उचित कदम नही।

इसे से प्रदेश में अनुसूचित जाति से संबंधित चमार बिरादरी या जो भी अन्य हो गांव स्तर पर विरादरी है, वह अपने आप को अपमानित महसूस करते हुए उनका मनोबल राजनीतिक प्रशासनिक सरकारी मानसिक समाजिक पंचायत स्तर पर गिर रहा है,यह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है।

हमारे पास सूत्रों से जो जानकारी कुछ नई छनछन कर पहुंची है, उसके अनुसार भी अब पंचायतों में सामान्य वर्ग के लोगों को " स्वर्ण "शब्द लिखा जा रहा है,अगर ऐसा है तो यह नई परंपरा प्रचलन किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है ।अनुसूचित जाति के लोगों को तो "हरिजन "लिखा ही जा रहा है, ये किसी भी दृष्टि से हमारे संविधान के अनुसूची के अनुच्छेद में दर्ज रिकॉर्ड से पूर्णतय से मेल नहीं खाता गलत कदम और गलत कार्रवाई संविधान मान्यता नही देता है । जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हरिजन शब्द लिखे जाने इसे अपमानजनक आपत्तिजनक मानते हुए इस पर पूर्णतया रोक प्रतिबंध लगा लगा रखा है

इसे से प्रदेश में विशेषकर अनुसूचित जाति के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, जो किसी गहरे जातिय राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रीय और स्थानीय पंचायत स्तर तक गहरे समाजिक जातिय षड्यंत्र की बू आ रही ईशारा करता है। सभ्य समरसता समतामूलक समाज के लिए उचित नहीं।

अतः आपसे आग्रह किया जाता है कि इस मामले को लेकर राज्य सरकार और संबंधित जिला उपायुक्तों और पंचायत स्तर के मामलों की उच्च स्तरीय जांच करवा कर इस सारे मामले की जवाब तलबी की जाए ताकि प्रदेश में जातीय माहौल खराब ना हो और अनुसूचित जाति के लोगों के राजनीतिक सामाजिक व्यक्तिगत स्थानीय पर मनोबल ना गिरे। ऐसी तमाम कारवाईयों को लेकर सख्ती से रोक लगाए जाने का आग्रह करते हैं और भविष्य में इस तरह कि पुनिवृत्ति नही हो इसको लेकर भी आपसे न्याय की उम्मीद करते हैं।

इस मामले में हुई उचित कार्यवाही से हमें भी शीघ्रअतिशीघ्र अवगत करवाने की चेष्ठा करें।

दिनांक 24/12/2021

भवदीय
कर्म चंद भाटिया,
प्रदेशाध्यक्ष
संत श्री रविदास धर्मसभा,
हिमाचल प्रदेश

24/12/2021

प्रतिलिपि :-आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ हेतु।
(1)माननीय मुख्यमंत्री,हिमाचल प्रदेश सरकार।
(2)समस्त जिला उपायुक्त हिमाचल प्रदेश ।